विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गये न्यायाधीश

578. श्री राम रतन राम: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त किये गये न्यायाधीशों की संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है.); और

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया था, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Withdrawal of frivolous suits

579. SHRI MENTAY PADMANABAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Supreme Court has asked Government to eschew frivolous suits;

(b) what steps have been taken by Government to reduce litigations from its side;

(c) whether any time-bound plan will be formulated to get all Departments of Government to withdraw frivolous suits;

(d) whether any such moves or steps have already been initiated before the censure by the Supreme Court; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARD-WAJ): (a) to (e) Yes, Sir. All Ministries/ Departments have been advised to consider the constitution of a Committee of senior officers to screen properly cases to be filed by Government and to scrutinise claims against Government with a view to avoiding unnecessary Government litigation, that Section 80 Civil Procedure Code notices should be carefully screened to redress genuine grievances of citizens at that stage itself, that principles of natural justice should be adhered to at every stage in the administration that efforts should be made to devise alternative procedures for resolving differences before they become lisputess in courts and that Government should be encouraged to refer lisputes involving Government Departments to Lok Adalats. More recently, a meeting of Chief Ministers and Chief Justices was held in New Delhi on 4 December, 1993 under the Chairmanship of the Prime Minister. The Chief Ministers and the Chief Justices *inter alia* recommended that every state should establish a Committee consisting of, among others, the Advocate General of the State, Remembrancer of Legal Affairs/Law Secretary (Judicial) of the State to go into the question of elimination of frivolous litigation and suggest appropriate remedial measures. It was also recommended that this Committee should consider the categories of cases which could be withdrawn if they were pending for more than a specified number of years.

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु की समीक्षा

580. श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमरीका, रूस और कई यूरोपीय देशों में न्यायाधीशों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए उन्हें सेवा-निवृत्ति आयु के दायरे से बाहर रखा गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो उन्हें 70 साल की आयु तक सेवा में रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार भी न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति आयु पर पुनर्विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ङ) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। अन्य देशों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने पर विचार किए जाने के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती।